International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 20-01-2021; Accepted: 05-02-2021; Published: 08-03-2021
www.socialsciencejournal.in
Volume 7; Issue 2; 2021; Page No. 01-06

उत्तराखण्ड में प्रव्रजनः एक समाजकार्य अध्ययन

भान सिंह[1], डॉ0 जे0 पी0 भट्ट[2]

[1] शोध छात्र, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे0 न0 ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, भारत

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे0 न0 ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखण्ड के जनपद टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक में प्रव्रजन की समस्या एवं उसके विभिन्न कारणों पर आधारित है। उत्तराखण्ड राज्य के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों से पलायन एक बड़ी समस्या बन गयी है जिसके कारण पर्वतीय जनपदों में सामाजिक–आर्थिक परिपेक्ष्य के साथ–साथ जनसांख्यिकीय संतुलन भी असंतुलित होता जा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य प्रव्रजन क्षेत्र में सूचनादाताओं की सामाजिक–आर्थिक की स्थिति एवं प्रव्रजन की समस्याओं के कारणों का अध्ययन करना था। विवराणत्मक शोध प्रारुप का चयन करते हुये शोधार्थी ने सभी 10 गाँवों से समग्र के रुप में कुल 1109 परिवारों का चयन किया जिसमें से निदर्शन के रुप 20 प्रतिशत के आधार पर 250 सूचनादाताओं का चयन किया गया। शोध पत्र के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर देखने को मिला तथा 18–29 वर्ष के लोगों का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे अधिक रहा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के मुख्य कारणों में कृषि से होने वाली आय में निरंतर कमी, जंगली जानवरों के द्वारा फसल नष्ट करने से कृषि कार्य में उत्पन्न अरुचि तथा खेतों में कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव जैसे कारण प्रमुख देखने को मिले जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार की दर अधिक हो जाने से ग्रामीण जन पलायन हेतु मजबूर हैं।

मूल शब्दः समाजकार्य अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक की स्थिति एवं प्रव्रजन की समस्या

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में 66 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों (पहाड़ी जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक) में रहती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति मैदानी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कठिन है। इसी कारण पर्वतीय जिले अधिक विकसित नहीं हो पाये हैं। पहाड़ी इलाकों में भूमि धारण बहुत ही कम और खंडित है। पहाड़ी इलाकों में केवल 10 प्रतिशत भूमि सिंचित है। पहाड़ों में अधिकांश ग्रामीण आबादी का निर्वाह कृषि पर होता है या रोजगार के लिए देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर जाती है। सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ी जिलों में विकास कम हुआ है लेकिन बिजली अधिकतर गाँवों तक पहुँच चुकी है। बुनियादी ढांचे में अंतर–जिला असमानता पर्वतीय और मैदानों के बीच आय और आजीविका के मामले में असमानता को बढ़ती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में गैर–कृषि पर आय निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। राज्य के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों से पलायन एक बड़ी समस्या बन गयी है, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्वासित बस्तियाँ या गाँव हैं, जिनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। पलायन की समस्या से निपटने के लिए पहाड़ी गाँवों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार भरसक प्रयास भी कर रही है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही हैं, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। अतः उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जानकारी एवं गंभीरता का आकलन करने हेतु आयोग स्थापित करने का फैसला किया और उत्तराखण्ड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया। इस आयोग के कार्यों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित कर पलायन की गंभीरता को कम करना एवं ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करना, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से हो, राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजनाओं की सिफारिशें प्रस्तुत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो, प्रमुख है।

प्रव्रजन को सामान्य अर्थों में लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण दूरी पर सापेक्षिक रूप में स्थाई तौर पर बसना माना गया है। प्रवजन स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है। हाल में ही भूगोलवेत्ताओं द्वारा जनसंख्या–गत्यात्मक तथा प्रवजन से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना आरम्भ किया है। प्रवजन एक भौगोलिक तथ्य है जो प्रत्येक युग में मानवीय आवश्यकता रहा है क्योंकि मानव की यह प्रवृत्ति रही है कि जिस स्थान पर जीवन कठोर होता है, उस स्थान को छोड़कर वह ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण करता है, जहाँ जीवन तुलनात्मक दृष्टि से सुगम होता है। प्रवजन के वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक मौलिक मापदण्ड दे पाना कठिन है। प्रवजन वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय अन्तः प्रदेशीय, अन्तः नगरीय तथा अन्तर–नगरीय हो सकता है। संख्या के आधार पर प्रवजन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकता है, यह राजनैतिक प्रवर्तित अथवा स्वतंत्र भी हो सकता है। प्रवजन क्रमशः भी हो सकता है अर्थात् गाँवों से नगरीय समूहों की ओर होता है। यह कहा जा सकता है कि प्रवजन ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों में समान रूप से होता है। प्रव्रजन (पलायन) के प्रति अप्रवासी व्यक्तियों की अभिवृत्ति अनेक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। कुछ परिस्थितियों में वे व्यक्ति जो मातृभूमि में रहते हैं उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वे डरते हैं कि उनके देशत्याग में उन्हे तथा उनके देश को कुछ हानियाँ होगी। कुछ अन्य स्थितियों में वे कुछ व्यक्तियों का

स्थान–परिवर्तन अच्छा समझते हैं, क्योंकि इनसे प्रवासी जहाँ जाते हैं, वहाँ के निवासी इतने निर्बल हो सकते है अथवा संख्या में इतने कम हो सकते हैं कि अप्रवासियों के प्रति उनकी अभिवृत्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। पहाड़ी जिलो जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का जिलावार सकल घरेलू उत्पादन देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों के 40 प्रतिशत से कम है। यह शायद उनकी अपेक्षाकृत कम आबादी और बड़े पैमाने पर ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था के कारण है। जब हम वर्ष 2009–10 और वर्ष 2016–17 के बीच राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की अनुमानित दर की तुलना करते हैं, तो यह पहाड़ी जिलों के मामले में लगभग 2 या 2.5 गुना और मैदानी जिलों के मामले में 3 गुना या उससे अधिक बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2011–12 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत था, तो वित्त वर्ष 2018–19 में घटकर 10.81 प्रतिशत रह गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 52.13 प्रतिशत से घटकर 48.28 प्रतिशत रह गया है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 33.88 प्रतिशत से बढ़कर 40.91 प्रतिशत हो गया है। (आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19, उत्तराखण्ड)

तालिका 1: प्रव्रजन करने वाले लोगों का विभाजन (युवा, मध्यम आयु वर्ग के लोग जिनके परिवार हैं, वरिष्ठ सेवानिवृत्त व्यक्ति)

ग्राम पंचायतों से जिला और आयु–वार प्रव्रजन (पलायन) की स्थिति (प्रतिशत में)			
जिला	**25 वर्ष की आयु से कम**	**26 से 35 वर्ष के बीच**	**35 वर्ष की आयु से अधिक**
उत्तरकाशी	30.68	36.56	32.77
चमोली	26.71	43.49	29.79
रुद्रप्रयाग	28.97	41.83	29.2
टिहरी गढ़वाल	29.26	40.92	29.82
छेहरादून	38.41	34.47	27.12
पौड़ी गढ़वाल	29.23	41.67	29.1
पिथौरागढ़	28.32	42.58	29.1
बागेश्वर	33.92	42.1	23.97
अल्मोड़ा	29.19	42.22	28.59
चम्पावत	25.23	45.49	29.29
नैनीताल	29.48	44.57	25.96
उधम सिंह नगर	16.66	43.34	40
हरिद्वार	13.99	52.79	33.22

स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड के सभी जिलों के 26 से 35 आयु वर्ग में अधिकतम प्रतिशत प्रवास दिखाया गया है। राज्य से पलायन करने वाले 26 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का औसत प्रतिशत 42.25 है, जो राज्य के युवा हैं।

प्रव्रजन के प्रमुख कारण

आधुनिक समय में पलायन की समस्या हेतु किसी एक कारण को जिम्मदार नहीं माना जा सकता है।उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में पलायन की दर प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है जिसमें रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी शिक्षा, खराब कृषि उपज (जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट करने की वजह से) एवं बहुत से कारण जिम्मेदार हैं जो कहीं न कहीं सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। उत्तराखण्ड में पलायन के प्रमुख कारणों में से कुछ निम्न हैं–

तालिका 2: पलायन के कारण

जिला	रोजगार	चिकित्सा सुविधाएं	शिक्षा	आधारभूत संरचना	खराब कृषि उपज	काम करने वाले परिवार का अनुसरण	जनवरों द्वारा कृषि उपज	अन्य
उत्तरकाशी	41.77	6.04	17.44	2.99	7.14	2.1	4.04	19.17
चमोली	49.3	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	3.09	4.87
रुद्रप्रयाग	52.9	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	5.11	5.72
टिहरी गढ़वाल	53.41	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52
छेहरादून	56.13	6.33	12.5	1.2	2.08	1.4	1.65	18.7
पौड़ी गढ़वाल	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	6.27	3.21
पिथौरागढ़	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	4.08	11.48
बागेश्वर	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65
अल्मोड़ा	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	10.99	6.02
चम्पावत	54.9	6.67	10.24	5.46	6.31	4.3	6.65	5.46
नैनीताल	53.7	7.79	10.37	4.96	4.94	2.1	6.38	9.76
उधम सिंह नगर	65.63	4.27	3.52	0.6	0.38	5.4	2.6	17.6
हरिद्वार	76.6	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	0.82	15.85

स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य से प्रव्रजन करने वाले कुल लोगों में से, रोजगार की खोज के कारण अधिकतम 50.16 प्रतिशत लोग प्रव्रजन कर जाते हैं। इसके बाद, 15.21 प्रतिशत लोगों के प्रवास के साथ शिक्षा पलायन के कारणों में दूसरे स्थान पर है।

उत्तराखण्ड में जिलावार आबादी विहीन गाँवों की स्थिति

उत्तराखण्ड जहाँ ग्रामीण स्तर से शहरी क्षेत्रों की तरफ तेजी से साल दर साल लोगों के द्धारा पलायन किया जा रहा है उससे विभिन्न जिलों के बहुत से गाँव आबादी विहीन हो गये हैं जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपितु सरकारों के लिए भी बहुत चिन्तनीय विषय बन गया है। उत्तराखण्ड की पलायन रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत कर रही है जिसमें सबसे अधिक गाँव पौड़ी जिले के तथा सबसे कम देहरादून जिले के आबादी विहीन हो गये हैं।

तालिका 3

जिला	कुल राजस्व गाँव/तोक/माजरा
उत्तरकाशी	70
चमोली	41
रुद्रप्रयाग	20
टिहरी गढ़वाल	58
देहरादून	07
पौड़ी गढ़वाल	186
पिथौरागढ़	75
बागेश्वर	77
अल्मोड़ा	57
चम्पावत	64
नैनीताल	22
उधम सिहं नगर	19
हरिद्वार	38
कुल आबादी विहीन गाँव	734

स्रोत : उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्रवास की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट।

साहित्य समीक्षा

रावत, पी0एस0 (1993), का अध्ययन "मागइग्रेशन एण्ड स्ट्रक्चरल चेंज ए स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इन गढ़वाल हिमालय" में लेखक ने इस अध्ययन में बताया कि प्रव्रजन मानव इतिहास की एक प्रमुख सामाजिक घटना रही है। उनका यह अध्ययन जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रव्रजन (पलायन) बहुत बड़ी संख्या में शहरों की तरफ हुआ है। जो कि देश के कुल पलायन के प्रतिशत का 15 प्रतिशत है, जिसमें 26.40 प्रतिशत पुरूष हैं जो पलायन कर जाते हैं। गढ़वाल हिमालय में अभी भी सुख–सुविधाएं, रोजगार, मील, कारखानों की कमी के कारण व सरकारी प्रयास सही दिशा में न होने से पलायन बढ़ा है।

जॉर्ज, फिलिप (1982), में "बर्थ डेथ एण्ड मॉइग्रेशन इन हिमालयास", का अध्ययन तत्कालीन उतरप्रदेश (अब उत्तराखण्ड) के हिमालयी भाग के टिहरी जनपद में विशेषकर जौनपुर विकासखण्ड में हुआ था। फिलिप द्वारा किया गया अध्ययन सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन है जिसमें न केवल जौनपुर, टिहरी के पलायन पर ही चर्चा कि गई है अपितु वहां के लोग, अधिवास, सांस्कृतिक पक्षों, रीति–रिवाजों उस समय में व्याप्त कुछ कुप्रथाओं अन्धविश्वास और बहुपति विवाह के विषयों पर भी खुल कर चर्चा की गई है।

खान, नजमा (1982) की पुस्तक "पैटर्न ऑफ रूरल ऑउटमाईग्रेशन, एक माईक्रो स्टडी" अपने इस अध्ययन में लेखक ने पलायन के कुछ नये पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है।अध्ययन में ज्ञात हुआ कि 66 प्रतिशत लोगों ने पलायन रोजगार के लिए किया एवं दूसरा सबसे बड़ा कारण औद्योगिकीकरण है। यह पलायन चेन पलायन कि भांति भी होता है जिसमें यदि एक ने पलायन कर दिया तो यह सूचना अन्य ग्रामीणों तक पहुंचती है और वे एक चेन में पलायन करते हैं।

प्रभाकर, एन.आर. (1985), का अध्ययन "इनटरनल माइग्रेशन एण्ड पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन इन इण्डिया" में लेखक ने पलायन को समझने का प्रयास किया है। उनके अध्ययन में बाल पलायन की समस्या भी उजागर हुई है जैसे कुछ ग्रामीण विभिन्न क्षेत्रों को रोजगार, मजदूरी के लिये जाते हैं और उनके बच्चे वही जन्म ले लेते हैं।

रावत, रूकमा (1997), ने अपने अध्ययन "रिटर्न माइग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट" में लिखा है कि पलायन एक वैश्विक प्रक्रिया है, जो मानव इतिहास के प्रत्येक स्तर पर देखा गया है। लेखक ने अपने अध्ययन में पाया कि एक लम्बे अर्से के बाद शहरी क्षेत्रों से लौटने के बाद प्रवासित लोग अपनी जीवन की कमाई से गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देते हैं।

शोध के उद्देश्य

- सूचनादाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पलायन के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत पट्टी उपली रमोली, रोणद रमोली, भदूरा, ओण तथा पट्टी रैका (धारमण्डल) के दस गाँव के अन्तर्गत किया गया। विवरणात्मक शोध प्रारूप का चयन करते हुए अध्ययन क्षेत्र के 10 गाँवों में समग्र कुल 1109 परिवारों में से 250 (20 प्रतिशत) सूचनादाताओं का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्रों, इन्टरनेट के माध्यम से किया गया।

तालिका 4: उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

विवरण	आवृति	प्रतिशत
उत्तरदाताओं का लिंग		
महिला	65	26-0%
पुरुष	185	74-0%
कुल	250	100-0%
उत्तरदाताओं की आयु		
18–25 वर्ष	04	01-6%
26–33 वर्ष	25	10-0%
34–41 वर्ष	36	14-4%
42–49 वर्ष	38	15-2%
50–57 वर्ष	55	22-0%
58–65 वर्ष	92	36-8%
कुल	250	100-0%
उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति		
विवाहित	218	87-2%
अविवाहित	03	01-2%
विधुर	05	02-0%
कुल	250	100-0%
उत्तरदाताओं की जाति		
ओ0बी0सी0	142	56-8%
अनुसूचित जाति	04	01-6%
कुल	250	100-0%
उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति		
अशिक्षित	52	20-8%
0–5 क्लास	26	10-4%
6–8 क्लास	36	14-4%
10वीं	36	14-4%
12वीं	76	30-4%
स्नातक	20	08-0%
परास्नातक	03	01-2%
पीएचडी	01	0-4%
कुल	250	100-0%

उपरोक्त सारणी के अन्तर्गत उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें लैंगिक आधार पर साक्षात्कार में पुरुष सूचनादाता महिला सूचनादाताओं की तुलना में अधिक सम्मिलित हुये। उत्तरदाताओं के आयु के स्तर के आधार पर शोध के लिए उपलब्ध सूचनादाताओं में से सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों तथा अधेड़ उम्र के लोगों का है जो संभवत इस बात के लिए इंगित करता है कि पलायन से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग अधेड़ उम्र के व्यक्तियों और बुजुर्गों पर पड़ा है जो पलायन के कारण अपने गांव में ही पीछे छूट गए हैं। उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर ज्ञात होता है कि कुल 250 सूचनादाताओं में से सर्वाधिक सूचनादाता (87-2%) लोग विवाहित हैं। जाति वर्ग के आधार पर सूचनादाता में सर्वाधिक अनुपात ओबीसी वर्ग के लोगों का है और उसके बाद स्थान सामान्य वर्ग के लोगों का आता है। टिहरी जनपद में प्रतापनगर ब्लाक पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आता है जिसके कारण सर्वाधिक प्रतिशतता ओबीसी वर्ग के सूचनादाताओं की है। उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के आधार पर ज्ञात होता है कि सूचनादाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत (30.4%) 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं उसके बाद सर्वाधिक सूचनादाता अशिक्षित पाये गये। प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि शोध संबंधित क्षेत्र में 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए लोगों का रुझान बहुत कम है।

प्रव्रजन हेतु उत्तरदायी कारण

जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के अन्तर्गत सूचनादाता द्वारा पलायन के मुख्य कारणों को जानने का प्रयास किया गया जिससे शोध क्षेत्र में विभिन्न समस्याऐं बनी हुयी हैं। पलायन का प्रभाव केवल क्षेत्र के विकास के लिए ही बाधक नहीं है अपितु जनसांख्यिकीय दृष्टि से भी बाधक है जिससे किसी भी क्षेत्र की लैंगिक स्तर में असन्तुलन पैदा हो जाता है।

तालिका 5: जेंडर एवं पलायन

क्र. सं.	सूचनादाता	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पुरुष	111	44.4 %
02	महिला	137	54.8 %
03	दोनों का	02	0.8 %
	कुल	250	100.00%

शोधार्थी द्वारा प्रव्रजन के सम्बन्ध में सूचनादाताओं से पलायन का सबसे अधिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें 54.8% उत्तरदाताओं ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक महिला समूह का पलायन हुआ है जबकि 44.4 % उत्तरदाताओं ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का पलायन हुआ है। केवल 0.8 % उत्तदाताओं ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों से दोनो समूहों का पलायन बराबर हुआ है। उपरोक्त डाटा इंगित करता है कि पलायन का सबसे ज्यादा प्रभाव महिला समूहों पर पड़ा है।

तालिका 6: आयु अनुसार पलायन दर

क्र. सं.	सूचनादाता	आवृत्ति	प्रतिशत
01	0.18	36	14.4 %
02	19.28	191	76.4 %
03	29.38	23	9.2 %
04	39.48	00	00
05	49.58	00	00
06	59+	00	00
	कुल	250	100.00%

आयु वर्ग के आधार पर पलायन की सम्भावना के सम्बन्ध में शोधार्थी के द्वारा जब सूचनादाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पलायन का सर्वाधिक (76.4 %) प्रभाव 19–28 आयु वर्ग के युवाओं पर पड़ा है जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, कृषि के प्रति अरुचि तथा बहुत से सम्बन्धित कारण जिम्मेदार हैं। इसके अलावा दूसरा सर्वाधिक प्रभाव 0–18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं पर देखने को मिला जिसका मुख्य कारण अच्छी एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करना है।

तालिका 7: कृषि कार्य में रुचि और पलायन

क्र. सं.	सूचनादाता	आवृत्ति	प्रतिशत
01.	कृषि में अरूचि	190	76.0 %
02.	रूचि है	05	02.0 %
03.	कह नहीं सकते	55	22.0 %
	कुल	250	100.00%

उपरोक्त तालिका में शोधार्थी के द्वारा उत्तरदाताओं का कृषि कार्यों के प्रति कम रुझान से पलायन पर प्रभाव को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने माना कि कृषि के प्रति लोगों का कम रुझान होना भी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होना भी एक मुख्य कारण है जिससे ग्रामीणजन रोजगार हेतु शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करने हेतु मजबूर हैं। जबकि 22.0 % उत्तरदाताओं ने इस बाबत हेतु जबाब देने में अपनी असमर्थतता व्यक्त की। उपरोक्त आंकड़ों पता चलता है कि ज्यादातर सूचनादाता लोगों की कृषि के प्रति उदासीन रवैये को पलायन का एक मुख्य कारण मानते हैं।

तालिका 8: कृषि के प्रति रुझान कम होने के कारण

क्र. सं.	सूचनादाता की प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि से होने वाली आय में निरंतर कमी	230	92.0 %
2	जंगली जानवरों के द्वारा फसल नष्ट करने से कृषि कार्य में उत्पन्न अरुचि	216	86.4 %
3	सिंचाई हेतु पानी की कमी	186	74.4 %
4	खेतों में कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव	186	74.4 %
5	अच्छे बीज और पौधों की उपलब्धता न होना	167	66.8%
6	चकबंदी न होना	112	44.8%
7	कृषि भूमि का बिखरा होना	101	40.4%
8	कृषि ऋण का आसानी से न मिलना	89	35.6%
9	कृषि उपकरण का न होना	80	32%

उपरोक्त तालिका के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा लोगों के कृषि के प्रति उदासीन रवैये के पीछे कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें सर्वाधिक कारणों में कृषि से आय में कमी 92.0 %, जानवरों द्वारा फसल नष्ट करना 86.4 %, सिंचाई हेतु पानी की कमी 74.4 %, उन्त बीजों की अनुपलब्धता 66.8% के प्रति सूचनादाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। जबकि कृषि ऋण का आसानी से न मिलना 35.6%, फसल का उचित मूल्य का न मिल पाना 34.8%, कृषि उपकरण का न होना 32%, आदि कारणों के प्रति सूचनादाताओं की प्रतिशतता काफी कम देखने को मिली। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय के द्वारा आय का निरन्तर कम होना जिसमें मौसमी खेती पर निर्भरता भी महत्वपूर्ण कारण है तथा जंगलों के आस–पास खेत होने के कारण जंगली–जानवरों का अतिक्रमण कर फसलों को बर्बाद करने से लोगों को खेती जैसे व्यवसाय से निरन्तर विमुख करता जा रहा है और लोग निरन्तर खेती छोड़ते जा रहे हैं।

निष्कर्ष

पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ पर आय के वैकल्पिक संसाधनों जैसे कृषि एवं कृषि से उचित आमदनी, उचित रोजगार, मूलभूत आवश्यकताओं जैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवायें और शिक्षण संस्थानों की कमी प्रव्रजन की मूलभूत समस्याओं में से रही हैं जिसके कारण लोग अपने पैतृक स्थानों को छोड़कर किसी अन्य अपरिचित स्थान पर बसने के लिये मजबूर हैं। ग्रामीणजनों के पलायन की एक मुख्य वजह उनके जीवन स्तर में सुधार व अधिक धन अर्जन, स्वास्थ्य सुविधा और बुढ़ापे की सुरक्षा को देखकर भी ग्रामीण पलायन कर गये (खान, नजमा (1982)। इसके साथ–साथ बाजारीकरण, औद्योगिकीकरण तथा वैश्वीकरण जैसे आधुनिक समस्याओं ने जहाँ लोगों का जीवन आसान बनाया तथा रोजगार के उचित अवसर हर एक व्यक्ति के लिए प्रदान किये वहीं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन के लिए मजबूर भी किया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही है, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। पूर्व में अधिक व अच्छी चिकित्सीय सुविधा न होने से शिशु मृत्यु दर अधिक रही है। जिससे गांवों की जनसंख्या अनुपात में कभी उतार–चढ़ाव देखने को मिलता था (जॉर्ज, फिलिप (1982)। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागमभाग, आपाधापी की जिन्दगी, उद्योगों कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं, वहीं गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है।

सुझाव

- उत्तराखण्ड के गाँवों से प्रव्रजन कम और नियंत्रित करने हेतु हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और सरकार को इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
- पलायन रोकने हेतु होमस्टे एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि बड़ा होटल बनाना हर किसी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है; इसलिए जो भी व्यवस्था उसके पास है वह उसको थोड़े धन व्यय के माध्यम से इस तरह के रोजगार को

बेहतर ढंग से कर सकता है; साथ ही पलायन की बेड़ियों को तोड़ सकता है।

- खेती के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के गाँव के किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसके बावजूद भी वह उस तरह की नकदी फसल का उत्पादन नहीं कर पाता है जिससे उसके परिवार का भरण–पोषण हो सके तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अतः खेती के क्षेत्र में हर्बल उत्पादन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उत्तराखण्ड सरकार भी इस तरह के कृषि कार्यों के लिए किसानों का होस्ला बढ़ा रही है।
- उत्तराखण्ड हिमालयी क्षेत्र का एक पर्वतीय राज्य है जहाँ की जलवायु बहुत ही सुन्दर व विभिन्नताओं भरी है। अतः उत्तराखण्ड के दूर–दराज के क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए पर्यटन बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसके लिए उत्तराखण्ड सरकार सदैव ही प्रयासरत रही है।
- पलायन का कोई एक कारण नहीं है और इसके लिए किसी एक परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। इसलिए औद्योगिकरण के क्षेत्र में लघु कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और पारम्परिक तौर पर जीवन पद्धति को आधुनिकता के साथ जोड़ा जाए और साथ ही सतत् विकास को आधार बनाकर नए दृष्टिकोण बनाए जाएं।
- समय के साथ पलायन के क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आया है; हमें यह जानना आवश्यक है कि वह कौन–सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके लिए लोग पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। हमें उन सभी पर गौर करना चाहिए साथ उन मूलभूत सुविधाओं पलायन क्षेत्र में विकसित करना चाहिए।
- उत्तराखण्ड के सभी क्षेत्रों में पलायन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है लेकिन पलायन रोकना आसान नहीं है उसके लिए हमें बेहतर विकल्प तलाशने होंगे और शुरुआत जमीनी स्तर से करनी होगी।

अंततः पलायन रोकने के लिए तो हम बहुत से प्लान बना सकते हैं लेकिन वह सभी तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम उनका पालन नहीं करते हैं। कोई भी सरकारी संस्था या गैर–संगठन तभी सफल होता है जब उसको वहाँ के लोगों (पलायन क्षेत्र) का समर्थन प्राप्त होता है। पलायन रोकने के लिए हमें अभी बहुत से प्रयास करने होंगे और यह समय–परिस्थिति अनुसार तय करना होगा कि हमें किन तथ्यों का अनुशरण करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. रावत, डॉ0 रूकमा (1997), रिटर्न माइग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सिद्धि पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, टिहरी गढ़वाल।
2. ओझा,रघुनाथ, (1953), जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन आचार्य नगर कानपुर–3, पृ0सं0–164
3. जॉर्ज फिलिप द्वारा (1982), "बर्थ डेथ एण्ड मॉइग्रेशन इन हिमालयास", भारी पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. खान नजमा, (1982), "पैटर्न ऑफ रूरल ऑउटमाईग्रेशन, एक माईक्रो स्टडी", बी0आर0 पब्लिशिंग कॉपरेशन, दिल्ली।
5. प्रभाकर, एन.आर. (1985),"इनटरनल माइग्रेशन एण्ड पॉपुलेशन रिड्रीस्टीब्यूशन इन इण्डिया", कानसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
6. चैरूनील, फ्रान्सिस, (1987), " पलायन, सेन्सस कोरलेट्स कॉनसिक्यावनसेस ट्रडस एण्ड पॉलिसिस, हिमालया पब्लिशिंग हॉउस, दिल्ली।
7. रावत, पी0एस0 (1993), "मागइग्रेशन एण्ड स्ट्रक्चरल चेंज ए स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इन गढ़वाल हिमालय", प्रकाशन सरीता बुक हाउस, दिल्ली (भारत)।
8. चौधरी, पदम सिंह, (2012) कुरूक्षेत्र, Publications Division, Min. of Information & Broadcasting , East Block-IV, Level-VII, R.K. Puram, New Delhi
9. चौधरी, पदम सिंह,(2012) कुरूक्षेत्र, Publications Division, Min. of Information & Broadcasting , East Block-IV,Level-VII,R.K. Puram, New Delhi
10. जिला घरेलू उत्पाद अनुमान, 2011–12 से 2016–17।
11. जिलावार प्रति व्यक्ति आय (उत्तराखण्ड), 2016–17।
12. उत्तराखण्ड का आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19।
13. उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायतों में प्रवासन की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट, पलायन आयोग (अप्रैल, 2018)।